उत्तर प्रदेश फोकस सेशन– सीआईआई इन्वेस्टमेंट कॉनक्लेव– गुड़गांव

बिना उत्तर प्रदेश के विकास के भारत की आर्थिक प्रगति को बनाए रखना मुश्किल

- *लघु उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री– उत्तर प्रदेश में निवेशकों का स्वागत है। वे नवीन उद्योगपरक नीतियों, सुविधाओं और पारदर्शी सरल प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधाओं और औद्योगिक विकास में सहभागी बनें।*
- *अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त– उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व आर्थिक व औद्योगिक क्रांति के द्वार पर खड़ा है*

गुड़गांव/लखनऊ, 04 नवम्बर, 2012:

गुड़गांव में आयोजित निवेश सम्मेलन – *इन्वेस्ट नॉर्थ* में उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च–स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे राज्य के लघु उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, भगवत शरण गंगवार ने आज यहाँ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

उपस्थिति निवेशकों व कई बिज़नेस समूहों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति में उद्यमियों को उपलब्ध कई आर्थिक और अन्य सुविधाओं के बारे में विशेष रूप से बताया। राज्य में उपलब्ध दक्ष मानव संसाधनए प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और तेजी से विकसित हो रही अवस्थापना परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस अवसर पर सीआईसीआई–केपीएमजी द्वारा *'उत्तर प्रदेश में निवेश के माहौल'* पर तैयार की गई रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

श्री गंगवार ने कहा–"निजी निवेश व सहभागिता के लिए उ.प्र. सरकार की गवर्नेन्स में सृजनात्मक परिवर्तन करने हेतु न केवल सरल व पारदर्शी प्रक्रियों को लागू करने की योजना है, अपितु पूरे प्रदेश में संतुलित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं।" उन्होंने आगे कहा– "उ.प्र. में उपलब्ध अपार मानव व अन्य संसाधनों, आकार व बढ़ते हुए उपभोक्ता आधार के कारण बिना राज्य के विकास के भारत का एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन पाना कठिन है।"

मंत्री जी ने उद्यमियों और उद्योगपतियों से उ.प्र. में उद्योग व आर्थिक विकास के त्वरित विकास के लिए आवश्यक सुझाव देने की अपील की। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार उद्यमियों के सुझावों पर विचार करते हुए नीति एवं प्रक्रियाओं में राज्य के साझा विकास के लिए गम्भीरता से विचार करेगी।

प्रदेश के निरन्तर औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विचारों और परिकल्पना पर प्रकाश डालते हुए श्री गंगवार ने बताया मुख्यमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि सरल प्रक्रियाएं, कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का जाल और ऊर्जा प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी), अनिल कुमार गुप्ता ने उ.प्र. में निवेशकों के लिए उपलब्ध असीमित सम्भावनाओं और इन सम्भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में विकसित की जा रही सुविधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा– *"उ.प्र. सरकार ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत व प्रक्रिया–विषयक निर्णय किए हैं। उत्तर प्रदेश आर्थिक व औद्योगिक क्रांति के द्वार पर खड़ा है, निवेशकों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे अपने व राज्य के संसाधनों का उपयोग कर विकास की इस धारा में शामिल हों।"*

आईआईडीसी ने विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि 3–4 वर्षों में विद्युत उत्पादन बढ़ाकर 12,000 से 15,000 मेगावाट किए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही वितरण और पारेषण तंत्र को मजबूत करने का काम भी किया जा रहा है। आरएपीडीआरपी, पार्ट–बी के तहत 26 शहरों में वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, जबकि पारेषण क्षमता को वर्तमान 11,000 मेगावाट से बढ़ाकर 30,000 मेगावाट किया जाएगा।

इस सत्र में प्रदेश में स्थापित व सफल उद्यमियों के ओर से बोलते हुए एचसीएल टेक्नोलॉजीस लि. के सौरभ अधिकारी ने राज्य सरकार के द्वारा उठाये जा रहे नए कदमों की सराहना करते हुए बताया कि उ.प्र. में वास्तव में अपार सम्भावनायें हैं और उन्हें अपने व्यवसाय को स्थापित और विस्तारित करने में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिला है।